नगर निगम ने भरा 1.65 करोड़ का जुर्माना, दोषी अफ़सरों की सेहत पर असर नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम 50 लाख का जुर्माना एनजीटी में व एक करोड़ पन्द्रह लाख का जुर्माना पर्यावरण बोर्ड में भर चुका है। परन्तु इससे भ्रष्ट एवं निकम्मे अफ़सरों की सेहत पर कतई कोई असर नहीं पड़ा, जो इसके लिये जिम्मेवार हैं, उनकी बेढंगी चाल एवं कार्यशैली ज्यों की त्यों बरकरार है।

समझने वाली बात यह है कि यह 1.65 करोड़ की रकम कहां से आई और कहां गयी। यह रकम जनता से बतौर टैक्स द्वारा, सरकार से प्राप्त ग्रांटों द्वारा और निगम की जायदादें बेचने से प्राप्त की गयी थी। यह रकम गयी है सरकार के खजाने में जहां से यह रकम देश भर की विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च होती है। यानी यही रकम या इसका कुछ भाग घूम फ़िर कर फ़िर किसी न किसी रूप में वापस भी आ जायेगा।

लेकिन, नगर निगम जो पहले से ही कंगाली में बेहाल है, आज उसका क्या होगा? उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेतन व भत्ते तो सभी निगम कर्मियों को मिलने ही है, आज नहीं तो कल मिल जायेंगे, जनहित में विकास कार्यों की तो चिंता ही किसे है? चिंता हो भी क्यों, इसके लिये तो ये अधिकारी बने ही नहीं हैं। ये लोग तैनात हैं केवल जनता के खून-पसीने की कमाई को चूसने के लिये।

इतना बड़ा जुर्माना भरने के बावजूद निगम अधिकारियों की कार्यशैली में कहीं भी कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा। सीवरेज का पानी ज्यों का त्यों जहां-तहां सड़कों पर भरा खड़ा है। सेक्टर 46 के लोग़ों की शिकायत पर एनजीटी ने कड़ा नोटिस लेते हुये बेशक नगर निगम पर 50 लाख का जुर्माना ठोक दिया, परन्तु इससे निगम अधिकारियों ने कतई कोई सबक नहीं सीखा। उसके बाद शहर में बढती गंदगी से होने वाले प्रदूषण का नोटिस लेते हुये पर्यावरण बोर्ड ने 1.15 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बरकरार है। यदि उक्त जुर्माने सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन एवं जायदादों से वसूल किये जाते तो स्थिति में पूर्ण सुधार होना निश्चित था। परन्तु शासन-प्रशासन ऐसा करने वाला है नहीं क्योंकि जनता का खून चूसने में वह भी बराबर का भागीदार है।

महकमे के मंत्री अनिल विज को सीआईडी विभाग कब्जाने की बेहद हड़बड़ी है। परन्तु जहां आंखों के सामने इतना घोटाला हो रहा हो, उसे देखते की फुर्सत नहीं।

भाजपा के नये अध्यक्ष नड्डा भी अमित शाह से कम नहीं

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश से आने वाले जय प्रकाश नड्डा बेशक गुजराती अमित शाह की तरह न तो तड़ीपार रहे हैं और न ही बड़े पैमाने पर किसी नर संहार के आरोपी, फ़िर भी वे अमित शाह से दो हाथ आगे बढने के लिये कोई कसर छोड़ने वाले नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का चढाव लेकर आये और उतराव के वक्त छोड़ चले। ऐसे में पुनः पार्टी के चढाव की ओर ले जा पाना कोई सरल काम नहीं।

इस सब के बावजूद नड्डा को अपनी उस फरेबी विद्या पर पूरा भरोसा है जो उन्होंने आरएसएस से ग्रहण की और जिसका अमित शाह व मोदी जैसों की प्रयोगशाला में बरसों तक पूरा अभ्यास किया। हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण करने के तमाम हथकंडे उन्होंने शुरू कर दिये हैं क्योंकि वे भली-भांति समझते हैं कि उनकी पार्टी एवं सरकार देश की जनता को न तो कुछ दे पाई है और न ही दे पाने की स्थिति में है। अभी तक देश को देने के नाम पर उनकी सरकार ने नोटबंदी, बेरोजगारी, घटती जीडीपी, गिरता रुपया, बढती महंगाई के अलावा छद्म राष्ट्रवाद, धारा 370, एनआरसी, सीएए आदि का झुनझुना ही दिया है। इन हालात में भाजपा के पास ले-दे कर एक ही सहारा बचता है हिंदुत्व, जिसके नाम पर देश में साम्प्रदायिक ज़हर फ़ैलाया जाय।

भ्रष्टाचार और लूट कमाई के मामले में भी नड्डा पीछे नहीं। इसका छोटा सा उदाहरण दिल्ली के एम्स में देखा जा सकता है। कांग्रेसी मनमोहन सिंह राज में नड्डा के चेहते हिमाचल काडर के एक आईएएस व एक आईपीएस अधिकारी एम्स में तैनात थे। उनके द्वारा मचाई गयी भारी लूट के चलते मनमोहन सरकार ने हरियाणा काडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को मुख्य विजिलेंस अधिकारी लगाया तो नड्डा को इतनी तकलीफ़ हुई कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद से कहकर चतुर्वेदी को एम्स से हटवाने के आदेश जारी करा दिये थे। परन्तु तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कह कर वह आदेश रद्द करवा दिया जिसके चलते कांग्रेसी राज में चतुर्वेदी अपने पद पर बने रह गये।

इस दौरान चतुर्वेदी ने करोड़ों रुपये के घोटाले पकड़ निकाले। लेकिन तभी भाजपा की मोदी सरकार आ गयी, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री बने, परन्तु नड्डा को इससे तसल्ली नहीं हुई और हर्षवर्धन से छीन कर खुद स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी ले ली। बस फ़िर क्या था, पहला निशाना ही चतुर्वेदी पर साधा और अपने दोनों लुटेरे अफ़सरों को उनके शिकंजे से निकाला। इससे समझा जा सकता है कि नड्डा के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को भी फलने-फूलने का पूरा मौका अमित शाह की तर्ज पर मिलेगा।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

फ़रीदाबाद डीसीपी विक्रम कपूर आत्महत्या काण्ड

खोदा पहाड़ निकाली चुहिया

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद डीसीपी विक्रम कपूर आत्महत्या काण्ड बीते साल अखबारों में छाया रहने वाला एक चर्चित मुद्दा था। बिकाऊ अखबारों ने उस वक्त सतीश कुमार (संपादक मजदूर मोर्चा) को पुलिसिया इशारे पर गुनहगार बनाना शुरू कर दिया था। जैसे-जैसे वक्त बीता यह प्रयास गायब होता गया; कारण, खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी झूठ को सच साबित करना पुलिस के लिए भी उतना ही मुश्किल सिद्ध हुआ जितना बिकाऊ अखबारों के लिए।

जिस डीसीपी कपूर के आत्महत्या के बाद पुलिस ने ये बताने का प्रयास किया कि उन्हें अपने अफसर की मृत्यु पर कितना गंभीर धक्का लगा है, उस पुलिस की असली बानगी यह है कि समय रहते अपने उसी अफसर को मृत्यु के मुंह से बचाने का तनिक भी प्रयास उसके आला अधिकारियों ने नहीं किया।

यहाँ पाठकों को बता दें कि 2-8 जून 2019 के मजदूर मोर्चा अंक में डीसीपी कपूर के सट्टा खिलवाने सम्बंधित छपी खबर को लेकर फरीदाबाद शहर के जाने-माने समाजसेवी और वकील डाक्टर ब्रह्मदत्त ने हरियाणा के डीजी लॉ एंड आर्डर के नाम 8 जून 2019 को एक शिकायत पत्र डाल कर एक्शन की मांग की थी।

इतना ही नहीं पद्मश्री डाक्टर ब्रह्म दत्त ने मजदूर मोर्चा की खबर गलत पाए जाने और स्वार्थपूर्ति के कारणों से छपने की सूरत में डीजी साहब से अखबार के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की मांग की थी। परन्तु डीजी लॉ एंड आर्डर को शायद यह गंभीर मामला जांच योग्य नहीं जान पड़ा और इस शिकायत का कोई जवाब तक नहीं दिया गया।

इसके बाद, पहले वाली शिकायत का

पद्मश्री समाजसेवी ब्रह्म दत्त ने सरकार पर उठाये सवाल

हवाला देते हुए डॉ. ब्रह्मदत्त ने दूसरी चिट्ठी फरीदाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के नाम लिखी, जिसकी कॉपी फिर से डीजी लॉ एंड आर्डर को भी भेजी गयी थी। उन्होंने 05/07/19 की इस चिट्ठी में पुलिस की छवि के खराब होने का हवाला देते हुए मजदूर मोर्चा अखबार 23-29 जून में छपी खबर की प्रति भी संलग्न की।

लेकिन आला अधिकारियों का हाल जस का तस रहा और किसी प्रकार का संज्ञान न लेते हुए कमिश्नर फरीदाबाद एवं डीजी लॉ एंड आर्डर दोनों ने अपनी निष्क्रियता का परिचय दिया।

डीसीपी कपूर की आत्महत्या के सन्दर्भ में डॉ. ब्रह्मदत्त ने तीसरी चिट्ठी 29 नवम्बर 2019 को कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए डीजीपी हरियाणा पुलिस मनोज यादव को लिखी जिसे कमिश्नर फरीदाबाद केके राव को भी कॉपी किया और साथ ही पिछली दो शिकायतों को भी संलग्न किया।

इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि यदि उनकी शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया गया होता तो डीसीपी कपूर की जान बच सकती थी। विभाग ने यदि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए डीसीपी कपूर पर कोई जांच बैठाई होती और उनका तबादला कर दिया होता तो शायद इंस्पेक्टर, जिसका जिक्र सुसाइड नोट में डीसीपी कपूर ने किया है से लगातार प्रताड़ना का उनका सिलसिला टूट गया होता और आत्महत्या की नौबत नहीं आ पाती।

यह कोई पहला अवसर नहीं है जब विभाग के भीतर इस प्रकार की परस्पर प्रताड़ना की शिकायत सामने आई हो। ऐसे में, यदि विभाग सजग होता तो अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच स्वस्थ पेशेवर संबंधों को लेकर और पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले जरूरतमंदों से सावधानीपूर्ण बर्ताव को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग एवम् काउंसलिंग चर्चाएं भी आयोजित करता।

दुर्भाग्यवश ऐसा न हो सका और हद तो तब हो गई जब पहले की दो शिकायतों के संदर्भ में डाली आरटीआई के जवाब में हरियाणा पुलिस का जवाब आया कि शिकायत पत्र ट्रेस नहीं हो सकते जबतक कि डॉ. ब्रहमदत्त डायरी नंबर में शिकायत की तारीख न बता सकें।

हैरानी की बात यह है डा. ब्रम्हदत्त को वांछित जवाब पुलिस विभाग से अब तक भी नहीं मिला है। इस लापरवाही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले जिन आला अधिकारियों को अपने महकमे की इज्जत सटोरियों के हाथ बिकते शर्म नहीं थी उन्हें आज अपने एक अधिकारी की जान जाने के बाद भी भविष्य में ऐसा न हो इसकी कोई परवाह नहीं। हाँ ठीकरा फोड़ने के लिए फिर किसी सतीश कुमार को अवश्य फंसा देंगे। नहीं फंसा सके तो भी कोई बात नहीं, न्यायपालिका कौन सा इन्हें इस अपराध की सजा देगी, रोज का काम है यह सब पुलिस के लिए।

अरावली जंगल बचाने की जन मुहिम-अरावली यात्रा

फ़रीदाबाद (म.मो.) 'सेव अरावली ट्रस्ट' की ओर से 19 जनवरी को इस साल की पहली अरावली यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा सुबह सात बजे गांव मोहबताबाद के 'झरना' मंदिर से शुरू होकर लगभग 4 किलो मीटर का चक्कर लगाकर वापिस झरना मंदिर पर ही खत्म हुई। अरावली जंगल और इसके पर्यावरण से परिचय कराने के लिये हर महीने ये यात्रा आयोजित की जाती है। यात्रा में हर बार पहले के मुकाबले ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं जो न सिर्फ़ इसके लोकप्रिय होते जाने का सबूत हैं बल्कि लोग़ों के अपने पर्यावरण के प्रति और ज्यादा जागरूक होने का भी प्रमाण है। इस बार की यात्रा में लगभग 200 लोग़ों ने हिस्सा लिया जिसमें बड़ी संख्या में महिलायें और बच्चे थे। यात्रा में लोग़ों ने यहां पाये जाने वाले पेड़-पौधों व पशु-पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल की।

इस अवसर पर सेव अरावली ट्रस्ट के प्रधान जितेन्द्र ने लोग़ों के सामने ट्रस्ट के लक्ष्यों और कामों के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने लोग़ों से जंगल बचाने, अधिक से अधिक पेड़ लगाने, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने। बंद करने व पानी संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि ये जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। सेव अरावली समूह के ही एक अन्य सदस्य रमेश श्योरान ने भी अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने बताया कि कई महीनों से आस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग और अमेरिका द्वारा छेड़े जा रहे युद्ध पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। इधर

अरावली के गुड़गांव के इलाके में बन्धवाड़ी तक और फ़रीदाबाद में सूरजकुण्ड रोड पर बड़े-बड़े फ़ार्म हाउस व बैन्कवैट हॉल बनाये गये हैं /बनाये जा रहे हैं, जिसके लिये हजारों पेड़ों को काटकर पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचायी गयी है। इस क्षति की पूर्ति दस गुणा नये पेड़ लगाकर भी नहीं हो पायेगी।

इस मुहिम को आगे बढाने के लिये लगातार मेहनत करने वाले सेव अरावली के वालंटियर बधाई व प्रशंसा के पात्र है। आशा और नये लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे। इसके लिये सेव अरावली का ट्रविटर और फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं या उनके 'व्हाटस एप ग्रुप' के सदस्य बन सकते हैं।